

अर्थव्यवस्था · Economy

केंद्रीय प्रतिपक्षों के लिए RBI के नए नियम और डिजिटल भुगतान में वित्तीय सुगमता सुधार

RBI ने वित्तीय बाजार स्थिरता हेतु सेंट्रल काउंटरपार्टीज के लिए संशोधित नियम जारी किए, दिव्यांगजनों हेतु डिजिटल भुगतान सुलभता अनिवार्य की और MSE ऋणों पर फोरक्लोजर शुल्क हटाने की पहल की।

अर्थव्यवस्था · Economy

1. CCPs के लिए RBI के नए नियम

- 2019 के पुराने नियमों को निरस्त कर नया विनियामक ढांचा जारी
- गवर्नेंस, डिफॉल्ट प्रबंधन और पूंजी पर्याप्तता के वैश्विक मानक लागू
- वित्तीय बाजारों में प्रणालीगत जोखिम रोकने में CCIL की भूमिका सशक्त

अर्थव्यवस्था · Economy

2. दिव्यांगजनों हेतु सुलभ डिजिटल भुगतान

- PoS मशीनें और डिजिटल भुगतान प्रणालियां सुलभ बनाना अनिवार्य
- बैंकों व PSPs को 1 महीने में DPSS को कार्ययोजना सौंपनी होगी
- सुरक्षा मानकों से समझौता किए बिना वित्तीय समावेशन को विस्तार

अर्थव्यवस्था · Economy

3. MSEs को फोरक्लोजर शुल्क से राहत

- सूक्ष्म व लघु उद्यमों के फ्लोटिंग दर ऋणों पर पेनल्टी हटेगी
- ऋण पुनर्वित्त और समय-पूर्व भुगतान में वित्तीय लचीलापन मिलेगा
- बैंकिंग क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और व्यापार सुगमता को बढ़ावा

परीक्षा के लिए तथ्य · Facts for Exams

याद रखें

Remember

नियामक अधिनियम

भुगतान और निपटान प्रणाली
अधिनियम, 2007 (PSS Act)

प्रमुख घरेलू CCP

क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
लिमिटेड (CCIL)

नोवेशन (Novation)

क्रेता के लिए विक्रेता और विक्रेता के
लिए क्रेता बनने की कानूनी प्रक्रिया

दिव्यांग अधिकार कानून

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

संबद्ध आरबीआई विभाग

भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
(DPSS)

सूक्ष्म उद्यम निवेश सीमा

₹1 करोड़ तक संयंत्र निवेश व ₹5 करोड़
तक टर्नओवर

अभ्यास प्रश्न • Practice MCQ

वित्तीय बाजारों में सेंट्रल काउंटरपार्टी (CCP) द्वारा निभाई जाने वाली केंद्रीय भूमिका के संबंध में 'नोवेशन' (Novation) से क्या तात्पर्य है?

- A पुराने ऋण को नए बॉन्ड में बदलना
- B मूल संविदा को समाप्त कर CCP का क्रेता के लिए विक्रेता तथा विक्रेता के लिए क्रेता बन जाना**
- C विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए कर छूट प्रदान करना
- D बैंकों द्वारा अनिष्पादित संपत्तियों (NPAs) को बट्टे खाते में डालना

उत्तर / Answer: B — नोवेशन वह प्रक्रिया है जिसमें केंद्रीय प्रतिपक्ष (CCP) मूल संविदा में मध्यस्थ बनकर स्वयं क्रेता के लिए विक्रेता और विक्रेता के लिए क्रेता की कानूनी देनदारी संभाल लेता है।

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

भारत में सेंट्रल काउंटरपार्टीज (CCPs) का विनियामक पर्यवेक्षण मुख्य रूप से किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है?

A कंपनी अधिनियम, 2013

B भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (PSS Act)

C बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

D विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA)

उत्तर / Answer: B — आरबीआई भारत में घरेलू और विदेशी केंद्रीय प्रतिपक्षों का नियमन व प्राधिकरण 'भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007' के तहत करता है।

पूरा लेख, PDF और रोज़ के अपडेट

Full article, PDF & daily updates

हिंदी और English दोनों में पढ़ें

aajkagk.com

पेज को **Follow** करें और **Share** करें

Follow the page & share with friends